

नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंधन उपकरण के संबंध में प्रशिक्षण की तिथियां निर्धारित

- हिन्दुस्तान एक्सप्रेस -
मुर्ना। होमगार्ड मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार कलेक्टर अंकित अस्थाना ने नगरीय निकायों में अनुभाग स्तर पर नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंधन उपकरण के संबंध में प्रशिक्षण की तिथियां निर्धारित की हैं। प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण जिला होमगार्ड इकाई द्वारा दिया जाना है। प्रशिक्षण में नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन उपकरणों की जानकारी, हवाई हमला, अग्नि आपदा संबंधी प्रशिक्षण तथा प्रथमोपचार की जानकारी दी जायेगी। प्राप्त जानकारी

के अनुसार अनुभाग अंबाह के अंतर्गत नगरपालिका पोरसा जनपद पंचायत पोरसा, नगरपालिका अंबाह, जनपद पंचायत अंबाह में 15 मई को प्रातः 11 से 2 बजे तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। अनुभाग डुरेना के अंतर्गत नगरपरिषद बानमोर, जनपद पंचायत मुरैना और नगरनिगम मुरैना में 16 मई को प्रातः 11 से 2 बजे तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अनुविभागीय अपने अपने क्षेत्रांतर्गत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था के नोडल अधिकारी होंगे। अग्नि आपदा संबंधी प्रशिक्षण नगरनिगम/नगरपरिषद तथा प्रथमोपचार का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा दिया जायेगा।

बाग सेवनिया में अब अपराधियों की खैर नहीं!



भोपाल। नेशनल हॉस्पिटल उठाएगा बड़ा कदम-थाना बाग सेवनिया क्षेत्र के दर्जनभर से अधिक प्रमुख स्थानों और चौराहों पर हार्ड-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अपराधों पर नकेल कसने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों के बीच अहम चर्चा हुई। नेशनल अस्पताल के मैनेजर श्रेयस ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। कैमरा इंस्टॉलेशन का काम जल्द शुरू होगा। इलाके की सुरक्षा को लेकर यह एक बड़ी और सराहनीय पहल मानी जा रही है।

आपरेशन सिन्दूर: सेना ने दिखा दिया भारत का 56 इंची सीना



- डॉ राघवेंद्र शर्मा -
आपरेशन सिंदूर ने और उसे अंजाम देने वाली भारतीय सेना ने देश के प्रत्येक नागरिक का सिर गवं से ऊंचा कर दिया है। वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस कार्रवाई को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी भारत पर हमला करना तो दूर उसकी ओर आंख उठा कर देखने का दुस्साहस भी ना कर सकेगे। प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप हमारी सेना के जबाज सिपाहियों ने भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे कर यह जता दिया कि पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, और यदि कोई हमें छेड़े तो फिर उसे हम छेड़ते नहीं। हलांकि भारत सरकार ने शत्रु देश का काफी नुकसान करने के बावजूद अपनी सैन्य कार्रवाई को औपचारिक रूप से युद्ध का नाम नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से हमारी सीमाओं के आसपास पड़ोसी देश के ड्रोन देखे गए, मिसाइल गिराने की असफल कोशिशें हुईं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य संसाधनों को हवा में ही नष्ट किया और शत्रु देश के अनेक एयरबेस उड़ाने में सफल रही। पाकिस्तान में संचालित आतंकियों के अनेक प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक ऐसे आतंकवादी मारे गए,पाकिस्तान सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर वहां आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे थे। उपरोक्त स्थानों पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर उन्हें दुनिया भर में शांति भंग करने के लिए निर्यात कर रहे थे। भारतीय सेना का आक्रमकता को देखते हुए तत् समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि परिस्थितियां औपचारिक युद्ध के मार्ग पर कदम आगे बढ़ा चुकी थीं। इसी से भयाक्रांत होकर पाकिस्तानी हुकमरान अमेरिकी दरबार में ढोक लगाने को मजबूर हुए। यही वजह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच

जैसा वह चाहता है अथवा जैसा उसने सोच रखा होता है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुश्मन की नापाक हरकतों को ठीक तरह से एक्सपोज किया जा सके, यह प्रयास भी बड़े पैमाने पर करने होते हैं। यह बताने के लिए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अब हमें कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि भारत समेत किसी भी देश में ऐसे तत्वों की उपस्थिति बनी रहती है जो हमारे बीच रहकर सुरक्षा संबंधी सूचनाओं को दुश्मन देश को भेजने का काम कर सकते हैं अथवा जाति संप्रदाय और समाज के नाम पर तनाव उत्पन करने के षड्यंत्रों में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया को ढाल बनाकर गलत अफवाहों फैलाना आज के युग में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उपरोक्त सभी हालातों को ध्यान में रखकर हमें पूर्व की अपेक्षा भविष्य में भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अचानक सक्रिय हो उठा है और उसे अपने क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा गया हो। यदि किसी जाने अनजाने व्यक्ति की कार्य प्रणाली अर्थात गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं तो इस बारे में पुलिस अथवा प्रशासन को तत्काल इतिला करना हमारा कर्तव्य होता है और दायित्व भी।

देश में ऐसे तत्वों का तावद भी कम नहीं है जो सदैव ही सरकार और सेना को हतोत्साहित करने या फिर उनकी कार्रवाई पर सवालिया निशान चप्पा करने की फिराक में बने रहते हैं। चूँकि पूर्व में ऐसे कड़वे अनुभव हो चुके हैं। इसलिए अबकी बार जब शत्रु देश की अकल ठिकाने लगाने का काम हुआ तो सेटेलाइट से उपरोक्त सैन्य कार्रवाई के फोटो संकलित किए गए और वीडियो भी बनाए गए, जिन्हें इस अघोषित युद्ध के साथ-साथ प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से हमारे सेना प्रमुखों द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक किया जाता रहा। नतीजतन इस बार समाज कंटक लोग अपनी हरकतों को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन यह आहंदा भी चुप रहेंगे, यह अपेक्षा करना श्वान की पूंछ के सीधे होने की कामना करने के समान है।

संभव है इनके द्वारा फारक अब यह पूछा जाए कि सरकार ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किए बगैर सैन्य कार्रवाई क्यों रोकी ? लेकिन सरकार इस बार उक्त षड्यंत्रकारियों से एक कदम आगे चलने की मंशा जाहिर कर चुकी है।

निर्माण इकाई के लिए भूमि-पूजन किया जाएगा। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सभी कार्षी समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बंगलुरु में निवेशकों की ओर से मिले रिस्पांस के लिये कार्टाटक की राजधानी बंगलुरु में पधारे सभी इंवेस्टर्स को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन्वेस्टर्स ने मध्यप्रदेश की नीति पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर आज बंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में शानदार प्रतिक्रिया मिली। पिछले दौर में मिले प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं। सभी विभागों की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता राज्य है। एनर्जी, आइटी, रिफ़ल एस्टेट, रेडीमेड गारमेंट्स और टूरिज़्म जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन तो हमारा प्रिय निवेश क्षेत्र है। स्वास्थ और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेशक आ रहे हैं। आज बंगलुरु से रेलवे कोच बनाने वाली कम्पनी बीईएमएल ने लगभग 2 हजार करोड़ का निवेश मध्यप्रदेश में करते हुए भविष्य में रेल के सभी कोच (डब्बे) बनने का काम करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की उद्योग हितैषी नीतियों के कारण उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल रही है।

इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्चुनिटीज इन मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंटरैक्टिव सेशन में इसमें टेक्स्टाइल में बेस्ट ऑपरेशन के एम डी श्री आर राजकुमार, नॉइज समूह के डायरेक्टर श्री मनीष सिंह चौहान, आईटी सेक्टर में एनएएसआर जीसीसी के सीईओ श्री ललित आहुजा, ओरेकल कापरिशन की नेशनल हेड (पॉलिसी) सुश्री अरश्लेश खान्देपरकर, इलेक्ट्रिक इंकिपमेंट्स सेक्टर में लैप इंडिया के एमडी श्री सुमित मिश्रा, हिन्दुस्तार कोका कोला के सीईओ श्री हर्ष भूटानी, हॉस्पिटालिटी सेक्टर में रायल ऑर्केड के संस्थापक एमडी श्री चंदेर बालजी, जीआईबीएस बिजनेस स्कूल के संस्थापक एमडी श्री रितेश गोयल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रीनको के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री बंडारु नरसिम्हा राव से वन-टू-वन चर्चा की।

बेंगलुरु में हुए %इंटैरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश% सत्र में उद्योग जगत के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र में प्रदेश निवेश संभावनाओं, ईई निवेश नीतियों, ईंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर व्यापक प्रेजेंटेशन दिए गए।

3 कर्पणियों के प्रतिनिधियों ने डिटेड अनुभव साझा

इंटैरैक्टिव सेशन में निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की प्रशंसा की। सेशन में श्री सुमित मिश्रा, एमडी, लैप इंडिया, श्री शांतनु राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीईएमएल और सुश्री सिम्था हेमिंगे, एमडी मार्केटिंग, एएनएसआर ने मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उनके द्वारा प्रदेश में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के संबंध में राज्य सरकार से मिली सुविधाओं के अपने अनुभव साझा किये।

विविध समाचार

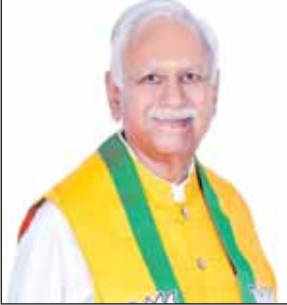
देवगढ़ पुलिस ने दबोचा फरार आरोपी

- हिन्दुस्तान एक्सप्रेस -



मुर्ना/जौरा। थाना देवगढ़ अंतर्गत हत्या के प्रयास के एक फरार 3000 रूपए के आरोपी को पुलिसने पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अरुण सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अपराध क्रमांक 7 सन 2025 हत्या के प्रयास का फरार आरोपी कल्ला उर्फ कमल किशोर सिकरवार निवासी छिनकरा गांव में छुपा हुआ है जिस पर से थाना प्रभारी ने पुलिस स्टाफ विपिन कुमार, चंद्रशेखर, दिलीप, नरेंद्र, बांकेलाल, नारायण, रजनी आदि को लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर 3000 के फरार हत्या के प्रयास के आरोपी कमल किशोर सिकरवार को पकड़ने में सफल हासिल की।

आतंकवाद के सफाया के लिए संकल्पबद्ध मोदी जी का



- सुरेश पच्चौी

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले ने पूरे भारत देश को झकझोर दिया। यह भारती की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। निर्दोष नागरिकों की उनके परिवारों के सामने हत्या, उनके धर्म के आधार पर, आतंक और क्रूरता का भयानक चेहरा था। यह देश की एकता और सौहार्द को तोड़ने का एक शर्मानाक प्रयास था। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे देश ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वे आतंकवादियों का खाल्ता करें।

भारत द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अटारी-वाघा सीमा बंद कर दी गई । द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिए गए। विवाद रोक कर दिया गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य प्रहार करने तक का हर कदम सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार ने उत्तेजना में कार्रवाई करने के बजाय रणनीतिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ठोस कार्रवाई के रास्ते को चुना। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, यह देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक बनकर सामने आया। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह, भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिज्ञा को साकार किया। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर और उनके प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक हमला किया, जिनमें प्रमुख है 1 सवाई नाला कैप मुजफ्फराबाद, 2 सैयदाना बिलाल कैप, मुजफ्फराबाद (जैश-ए-मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र) 3 बरनाला कैप, बीरबगढ़ 4 अब्बास कैप, कोटली (एलएटी का फिदायीन प्रशिक्षण केंद्र) 5 सरजाल कैप,

ग्वालियर, गुरुवार 15 मई 2025

भारतीय सेना के सम्मान में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, बैठक में हुआ निर्णय



गया। भारतीय जनता पार्टी महाराज अग्रसेन मंडल की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश शेखावत विशेष अतिथि के रूप में मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन पाठक महाराजा अग्रसेन मंडल के अध्यक्ष महेश भदोरिया सबसे पहले बैठक में मुख्य अतिथियों द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्रों पर माला अर्पण कर बैठक शुभारंभ किया। गया मंडल के मंत्री हरिओम राय द्वारा हरिओम राय द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद मंडल की बैठक में मुख्य अतिथि

के रूप में पधारे ओमप्रकाश शेखावतजी ने अपनी बात रखी कल जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें अपनी भारतीय सेना का गौरव बढ़ाना है। उन्होंने और हम भारतीय सेवा के साथ में हैं जो भारतीय सेना ने अपना पराक्रम

पाकिस्तान तो दिखाया है। उनके सम्मान में एक तरंग यात्रा बनती है। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर वोटिंग पोस्ट नहीं होंगे। यात्रा पूरी तरह देश को समर्पित रहेगी। इसमें नारे भी सिर्फ भारतीय सेना जिंदाबाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लंगेंगे। मुख्य अतिथि में सभी आदि से किस तिरंगा यात्रा में

पाण्डेय जनसुनवाई में मौजूद नहीं थे। कलेक्टर ने जनसुनवाई उपस्थिति के पत्रक बुलवाकर देखा एवं उनके द्वारा पाया गया कि एएसएलआर जनसुनवाई में मौजूद नहीं रहते है और कार्यलय से बिना बताये निकल जाते है।उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम विपरित है एवं शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं

अवहेलना अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छचारिता को दर्शाता है। इन सब आरोपो को मानते हुये कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख नरेंद्र कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरैना रहेगा।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि उसके पंजाब प्रांत में स्थित थे। शायद पाकिस्तानी सेना को अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पंजाब प्रांत के भीतर भी हमला कर सकती है। पाक के 11 हवाई अड्डे भारतीय सेना द्वारा मिट्टी में मिला दिए गए, जिनमें प्रमुख थे बहावलपुर, नूरखान, जैकोबाबाद, सरगोहा, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, स्कारू, मुलतारी । आपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कूटनीतिक कामयाबी मिली है । पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक चेराबंदी में अमेरिका, साउदी अरब, यू.ए.ई. जैसे बड़े देशो का समर्थन हासिल किया। आज पाकिस्तान कूटनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पड़ चुका है।यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी वैचारिक असहमतियों से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की कूटनीतिक चेराबंदी ही है कि पाकिस्तान चार दिनों में ही घुटनों पर आ गया। दस मई को पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे धुआं-धुआं हो जाने के बाद पाक सरेंडर कर सीजफायर के लिए अपने डीजीएमओ के जरिए गुहार करने लगा। भारत ने दो ट्रंक फैसला किया कि भविष्य में अगर आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि आपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसके माध्यम से दुनिया को भारत की ओर से यह संदेश दिया गया कि बबरता का सामना संतुलित और सटीक बल प्रयोग से किया जाएगा। आतंकवाद के साथ पड़ोसी देश की साठगंठों व कूटनीतिक आवरण या परमाणु हथियारों की धमकियों से जुड़ी बयानबाजी के पीछे नहीं छिप सकेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने लगातार आतंकवाद की बढ़ावा दिया है । उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां अतंतः

सम्मिलित होने का बात रखी ओबेविषयसली लोक इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो।

बैठक में ज़िले और मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष केशव मांझी, मंडल के पूर्व महामंत्री छोटे सिंह तोमर, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल की महामंत्री ज्योति पाठक, आरती तोमर, नेहा शर्मा, सुग्रीम राय, पूर्व पार्षद जय सिंह सोलंकी, मंडल के मंत्री हरिओम राय, विनोद बाथम, वृंदावन माहौर आदि लोग उपस्थित थे। अंत में बैठक का आभार मंडल के मंत्री हरिओम राय जी द्वारा किया।

(लेखक भारत सरकार में रक्षा उत्पादक राज्य मंत्री रहे हैं)

संपादकीय

‘आपरेशन सिंदूर’ से साफ संदेश, आतंकवाद पर वार नहीं रुका है, सिर्फ बदली है रणनीति



संघर्ष किस हद तक पहुंच जाता, कहना मुश्किल है। इसलिए सैन्य संघर्ष पर विराम और आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति बनाना जरूरी था। भारत शुरू से कहता रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत-पाक संघर्ष विराम के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आतंकवाद और बातचीत या व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। सैन्य संघर्ष फिलहाल स्थगित किया गया है, वह समाप्त नहीं हुआ है। आपरेशन सिंदूर अब भारत की नई नीति है। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया था कि संघर्ष विराम अस्थायी है, सेना नए अभियान के लिए तैयार है। फिर राष्ट्र के नाम संबोधन के अगले दिन प्रधानमंत्री आदमपुर वायुसेना अड्डे पर सैनिकों से मिलने गए और वहां भी यही संकेत दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति यथावत है। इस तरह अचानक किए गए संघर्ष विराम के फैसले को लेकर पिछले दो-तीन दिनों से जो अटकलें लगाईं और सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर विराम लग जाना चाहिए। सेना बार-बार कहती रही है कि उसका सैन्य अभियान आतंकवाद के खिलाफ था। अब भी प्रधानमंत्री ने वही बात दोहराई है कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना ही हमारा असल मकसद है। प्रधानमंत्री ने प्रकाशित से पाकिस्तान और भारत के बीच के मसलों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रस्ताव पर स्पष्ट कह दिया कि जब भी बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर और आतंकवाद पर ही होगी। पहलगाम हमले के बाद आपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए थे। इसके साथ ही सरकार ने सप्रमाण दुनिया भर को बता दिया था कि उसका मकसद पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि वहां चल रहे आतंकी संगठनों पर हमला करना था। मगर पाकिस्तान ने उसके जवाब में भारतीय सीमा के नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया था। ऐसे में स्थिति लगातार संघर्ष के बढ़ते जाने की बन गई थी। संघर्ष किस हद तक पहुंच जाता, कहना मुश्किल है। इसलिए सैन्य संघर्ष पर विराम और आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति बनाना जरूरी था। भारत शुरू से कहता रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फिर, उसका जोर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और दुनिया की शीर्ष शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने पर है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक सैन्य संघर्ष में उलझे रहना कोई समझदारी की बात नहीं होती। फिर, जिस तरह के वैश्विक समीकरण बने हैं, उसमें यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित रह पाता, यह कहना भी मुश्किल था। इसके अलावा, दुश्मन देश के साथ तनाव के वातावरण में अगर कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। संघर्ष विराम के बाद भी सीमा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी धमी नहीं है। सेना ने आशंका जाहिर की है कि ऐसा वह आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और हमारी चौकियों पर कब्जा करने की मंशा से कर रही होगी। शोपियां में तीन आतंकवादियों के मार गिराने की घटना भी संघर्ष विराम के बाद की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता।

बीच में स्कूल छोड़ने

के लिए आखिर किसकी

जिम्मेदारी बनती है-

सरकार में बैठे हुए

नेताओं की, नौकरशाहों

की, शिक्षा विभाग की

या फिर गुरुजनों की?

कोई सर्वस्वीकार्य या

सहमत करने वाला

जवाब नहीं आ पाता तो

उसके बाद ठीकरा भोले-

भाले अभिभावकों पर

फूटता है। जिम्मेदारी

किसी की भी हो और

जिम्मेदार किसी को मान

भी लिया जाए। अगर

देश का भविष्य सुरक्षित

हाथों में रखने की मंशा

हो तो बीच में स्कूली

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों

की संख्या कम की जा

सकती हैं।

‘

ड्रॉपआउट कम करने का पाद, स्कूल का आनंदमय माहौल और जिम्मेदारी की जरूरत

जितने भी अध्यापक या शिक्षा प्रशासन के लोग हैं, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में आनंदमय वातावरण बनाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी दस-बीस दिन से नहीं आ रहा है तो उसकी समस्या की पहचान कर, उस पर गंभीरता से विचार करने और फिर से उसको विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

लंबे समय से शैक्षणिक जगत में एक सवाल आज भी अपना उत्तर खोजने में नाकामयाब रहा है कि आखिर शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में कैसे रोका जा सकता है। अगर एक बार बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर चुका है तो पूरे वर्ष भर उसे कक्षा में कैसे रखना है। नियमित विद्यार्थियों का सरकारी स्कूलों में आनंदमयी शिक्षा न होने के अभाव में बच्चों का शैक्षणिक विकास ठप होता जा रहा है। बीच में स्कूल छोड़ने के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है- सरकार में बैठे हुए नेताओं की, नौकरशाहों की, शिक्षा विभाग की या फिर गुरुजनों की? कोई सर्वस्वीकार्य या सहमत करने वाला जवाब नहीं आ पाता तो उसके बाद ठीकरा भोले-भाले अभिभावकों पर फूटता है। जिम्मेदारी किसी की भी हो और जिम्मेदार किसी को मान भी लिया जाए। अगर देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में रखने की मंशा हो तो बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में हमेशा की तरह एक कालम यह भी है- बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है। मगर अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि आजादी के बाद हम कभी भी नामांकित सभी बच्चों को शत-प्रतिशत, नियमित रूप से, पूरे वर्ष विद्यालय में बनाए रखने में कामयाब नहीं रहे। हम कभी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम कर पाएंगे, उसके समांतर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रूझान है या नहीं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रति रूझान थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है तो वह है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम रही है। दूसरी ओर, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की समस्या केवल सरकारी स्कूलों में ही क्यों



देखी जाती है, इस पर कभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। होना तो यह चाहिए की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हमें इस पर विचार करने के लिए एक-एक विद्यालय को इकाई मानकर कार्ययोजना बनानी चाहिए। हम ‘प्रवेशोत्सव’ के माध्यम से बच्चों का स्कूल में नामांकन करते हैं। संबंधित विद्यालय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा में उस क्षेत्र के लगभग सभी बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए उन बच्चों की स्कूलों में बने रहने संबंधी कार्य योजना बनाई जाए। इसके विपरीत होता यह है कि हम बार-बार निजी क्षेत्र को कोसते रहते हैं। जबकि निजी क्षेत्र में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उन्हें वहां अध्ययन करने पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। चिंता का विषय यह होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन के बावजूद बच्चों में वहां पढ़ाई के प्रति स्थिरता कैसे रहे, उन्हें बीच में स्कूल छोड़ने से कैसे रोका जा सके। अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेहतर भविष्य के लिए विद्यार्थियों का ‘ड्रॉपआउट’ कम करना होगा। अक्सर यह कहा जाता है कि इस पर ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया

जाएगा, लेकिन अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह पक्ष सामने आता है कि बिखरे हुए प्रयासों से विद्यार्थियों के बीच में स्कूल छोड़ने को नहीं रोका जा सकेगा। उनकी पढ़ाई बीच में छूटना सकेगा तो ठोस इच्छाशक्ति और क्षेत्र विशेष के विद्यालय की कार्य योजना से। संबंधित विद्यालय की कार्य योजना की सफलता के लिए नियमित रूप से उसकी निगरानी की जानी चाहिए। दरअसल, इस समस्या की जड़ में आए ज्यादातर विद्यालय इस पेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए संबंधित विद्यालयों को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग की ओर से मदद की जानी चाहिए। विद्यालय के प्रधान को नोटिस देकर बात समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या की निगरानी कक्षा एक से ही अलग-अलग कक्षाओं की होनी चाहिए। हम इसे राष्ट्रीय समस्या या प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश या जिले की समस्या मानकर ‘ड्रॉपआउट’ में एकरूपता ले आते हैं। यहां स्पष्ट करने की जरूरत है कि ‘ड्रॉपआउट’ एकरूपता की समस्या नहीं है। हमें विचार करना चाहिए कि पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या एक जिले

की भी एक जैसी नहीं होती, बल्कि एक विद्यालय को इकाई मानकर स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम किया जा सकता है। जबकि हम ऐसे बच्चों की संख्या को कम करने के बजाय अध्यापकों की कमी, संसाधनों का अभाव आदि की समस्या पर जोर ज्यादा देते हैं। इस संबंध में देखें तो जितने भी अध्यापक या शिक्षा प्रशासन के लोग हैं, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय में आनंदमय वातावरण बनाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी दस-बीस दिन से नहीं आ रहा है तो उसकी समस्या की पहचान कर, उस पर गंभीरता से विचार करने और फिर से उसको विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अगर एक बार बच्चा कुछ दिन स्कूल नहीं आता है तो वह आएगा ही नहीं। अगर हम उनके अभिभावकों से संपर्क में रहेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस काम के लिए विद्यालय से बाहर अभिभावक, शिक्षाविद और शिक्षक मिलकर प्रयास करेंगे तो स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने में सफलता हासिल की जा सकती है।

मजाक बना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं प्रासंगिकता खो रही

संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक आइएमएफ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए कई बार आवाज उठाई गई है क्योंकि बदलते परिवेश में ये अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विश्व बैंक आइएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अपने उद्देश्यों के प्रति वास्तविक समर्पण लंबे समय से संदिग्ध ही रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डालर का नया लोन भारत के कड़े विरोध के बावजूद दे दिया। इसके साथ ही उसने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत मिल रहे करीब 60 हजार करोड़ रुपये की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी। इससे

पाकिस्तान को अगली किस्त के करीब 8,542 करोड़ रुपये मिलेंगे। आइएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही राशि पर चिंता जताते हुए कहा था कि इस फंड का दुरुपयोग वह आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर सकता है। भारत से सैन्य टकराव के बीच आइएमएफ का यह निर्णय फंडिंग एजेंसियों और दानदाताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। यह आइएमएफ के उस निर्णय के भी ठीक विपरीत है, जिसमें फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद आइएमएफ ने उसके साथ अपने वार्षिक परामर्शों को रोक दिया था। खेद की बात है कि इस बार वह इतना भी नहीं कर सका। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, आइएमएफ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए कई बार आवाज उठाई गई है, क्योंकि बदलते परिवेश में ये अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विश्व बैंक, आइएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अपने उद्देश्यों के प्रति वास्तविक समर्पण लंबे समय से संदिग्ध ही रहा है। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्धों के साथ-साथ बड़ती वैश्विक समस्याओं के कारण संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन भी अपने उद्देश्यों में नाकाम रहा है। दुनिया में यह भावना बढ़ रही है कि एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र लगातार अप्रभावी होता जा रहा है। आइएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में नेक इरादों के साथ हुई थी। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 191 है। पिछले कुछ वर्षों में आइएमएफ अपनी भूमिका से न्याय



नहीं कर पाया है। आइएमएफ 2008 के वित्तीय संकट की निगरानी और उसका आकलन करने में भी पूरी तरह विफल रहा था, जबकि लेहमैन ब्रदर्स के पतन से कुछ दिन पहले ही ऐसी आशंका बढ़ चुकी थी। आइएमएफ ने शायद ही कभी किसी भी संकट से निपटने की वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्षमता के बारे में आशावादी रुख दिखाया हो। पाकिस्तान 35 वर्षों में

28 बार आइएमएफ से मदद ले चुका है। अगर पहले दिए गए कर्ज का पाकिस्तान ने सही उपयोग किया होता, तो उसे बार-बार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब फिर नया लोन दिया जाना आइएमएफ की मंशा के साथ-साथ उसकी निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। निश्चय ही नए कर्ज के दुरुपयोग का खतरा अधिक है। आइएमएफ के बड़े कर्जदार देशों में

पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, जिससे उसने 8.3 अरब डालर का कर्ज ले रखा है। संयुक्त राष्ट्र की 2021 की रिपोर्ट स्पष्ट संकेत करती है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के बावजूद वहां के कामकाज में सेना का पूरा हस्तक्षेप रहता है। सेना वहां की अन्य अनेक नीतियों के साथ आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करती है। यदि पाकिस्तान ने आइएमएफ की मदद का विकास कार्यों में उपयोग किया होता, तो पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 168वें स्थान पर नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान का हर बच्चा अपने सिर पर करीब 85 हजार रुपये का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में वेतन और सब्सिडी जैसे खर्च से लेकर तेल और गैस का आयात बिल तक सब कुछ कर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण उसकी जीडीपी का 69.4 प्रतिशत हो गया है। आइएमएफ का उद्देश्य विश्व की सभी मुद्राओं को स्थिर रखने और मुक्त व्यापार की सुविधा देना था, परंतु दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से आइएमएफ इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके पास गलत परियोजनाओं के लिए जवाबदेही का भी अभाव है। कर्ज में डूबे देशों द्वारा डिफाल्ट को रोकने के लिए नए ऋण देने की आइएमएफ की नियमित प्रथा एक नैतिक जोखिम पैदा करती है। इसीलिए भी आइएमएफ की प्रणाली पर कड़ी निगाह रखने के साथ उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्व बैंक और आइएमएफ को आंतरिक न्याय, जवाबदेही और निगरानी कार्यों का पुनर्गठन भी करना चाहिए। बोर्ड की बैठकों और वॉरंटिंग में अधिक पारदर्शिता लाना भी जरूरी है।

वैश्वीकरण और संघर्ष समाधान के नए तरीकों से जूझ रहे विश्व में इन संगठनों की भूमिका पर लगातार प्रश्न उठ रहा है। ज्यादातर संगठन अपने उद्देश्यों में असफल साबित हो रहे हैं। यदि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता तो उनमें व्यापक सुधार तो जरूर किया जाना चाहिए। आइएमएफ को फंड देने के तरीकों में सुधार शुरू करने का यही सही समय है। इसके साथ ही बेलआउट कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की भी समीक्षा करनी होगी। 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुई जी 20 बैठक के दौरान आइएमएफ सहित अन्य बहुवैश्वीय संस्थानों में सुधार पर बात हुई थी। दुनिया को सोचना होगा कि संयुक्त राष्ट्र, आइएमएफ, विश्व बैंक आदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में निवेश की गई वित्तीय और बौद्धिक पूंजी का विश्व भर के लोकतंत्र में कैसे बेहतर उपयोग हो। आज दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को इनके पारदर्शी कार्यों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश स्वाभाविक था। मगर सवाल है कि क्या ऐसे आक्रोश को किसी उन्माद में तब्दील होने की इजाजत दी जा सकती है, जो अपने ही देश के जिम्मेदार अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ आक्रामक दुर्व्यवहार पर उतर आए? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष संबंधी सूचनाएं आधिकारिक रूप से देश के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिसरी लोगों तक पहुंचा रहे थे। सचिव के रूप में विक्रम मिसरी लोगों तक पहुंचा रहे थे।

आतंकी हमले के बाद ट्रोलर्स का हमला, जब अपने ही निशाने पर आ गए जिम्मेदार अफसर



सामना करना पड़ा। उनकी बेटी के संपर्क को सार्वजनिक कर दिया गया। सवाल है कि जिन लोगों ने विदेश सचिव और उनके परिवार के खिलाफ इस हद तक आनलाइन दुर्व्यवहार किया, क्या उन्हें कहीं से भी देश के प्रति निष्ठा और कर्तव्य भाव रखने वाला माना जा सकता है? इन्हीं लोगों ने पहलगाम में मारे गए नौसेना अधिकारी की पत्नी के खिलाफ भी अशोभन टिप्पणियां की थी। इन घटनाओं के जोखिमों को देखते हुए ही

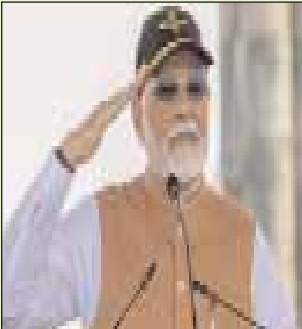
कई नेताओं और पूर्व राजनयिकों ने एकजुट होकर विदेश सचिव का समर्थन किया है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर गहरी चिंता जताई और इसकी सख्त निंदा की है। पहलगाम में आतंकवादियों के बर्बर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर जो कार्रवाई की, वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इसका अर्थ है कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी।

मगर भारत सरकार ही अंतिम प्राधिकार है, जो यह तय करेगी कि आतंकवादियों के विरुद्ध कैसी प्रतिक्रिया हो। भारत की कार्यवाई के जवाब में पाकिस्तान ने अनुचित तरीके से गोलाबारी की, तो भारत ने उसका भी उचित जवाब दिया। विडंबना यह है कि आनलाइन दुर्व्यवहार करने वालों की कई बार अनदेखी कर दी जाती है। जबकि ऐसे लोगों से कानून के दायरे में उचित तरीके से निपटने की जरूरत है, ताकि इंटरनेट की दुनिया सच्चे लोगों के लिए सुरक्षित हो।

प्रधानमंत्री के भाषण का सार यही है कि भारत ने आतंक के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली है, बल्कि आतंकियों एवं उनका साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया है कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ न बहने का क्या मतलब है।

भारत का अमेरिका को जवाब, तीसरे पक्ष की कोई एंट्री नहीं

एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है लेकिन कम से कम इससे यह तो समझ आ ही गया कि अमेरिका से संबंध बढ़ाते समय सावधान भी रहा जाना चाहिए। उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए देर भी नहीं क्योंकि ट्रंप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं रहते। प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और फिर आदमपुर एयरबेस पर आपरेशन सिंदूर की सफलता और सेनाओं के शौर्य को रेखांकित करते हुए ऐसी कई बातें कहीं, जिन पर पाकिस्तान के साथ ही विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका को ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री के भाषण का सार यही है कि भारत ने आतंक के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली है, बल्कि आतंकियों एवं उनका साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय किया है कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ न बहने का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाकिस्तान से



केवल आतंक और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर बात होगी। यह बयान साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी ध्यान में रखकर दिया गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थमने का श्रेय लेने के साथ ही कश्मीर मसले पर बीच-बचाव करने की भी पहल की। हद तो तब हो गई, जब उन्होंने यह कह दिया कि दोनों देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के कारण सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए। ट्रंप के बयान की सिर से खारिज करना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि यह जम्मू-कश्मीर पर भारत की नीति से मेल नहीं खाता, बल्कि इसलिए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से आतंक को व्यापार से जोड़ रहे हैं। यह

किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता और भारत को तो कदापि नहीं, जो ऐसे आतंकवाद से जूझ रहा है, जिसका पोषण पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आतंक और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। निःसंदेह ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति हैं और किसी भी मसले पर कुछ भी अनाप-शनाप कह जाते हैं और फिर उससे पलट भी जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें जवाब न दिया जाए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दो टुक कहा कि आपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर उसे रोकें जाने तक अमेरिकी नेताओं से व्यापार के विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई और जम्मू-कश्मीर पर हमारी नीति यथावत है। एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी, जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम इससे यह तो समझ आ ही गया कि अमेरिका से संबंध बढ़ाते समय सावधान भी रहा जाना चाहिए। उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भी मैं नहीं, क्योंकि ट्रंप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं रहते। वह प्रायः अपने कहे के उलट काम करते हैं।



बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया बोले-रोहित-विराट ग्रेड ए+ में बने रहेंगे

वे अभी भी भारतीय क्रिकेट का हिस्सा, दोनों ने टी-20 और टेस्ट से संन्यास लिया

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के, + ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने का फैसला किया है, भले ही वे टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पिछले महीने बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। इसमें दोनों खिलाड़ी ग्रेड ए+ में थे।

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, कोहली और रोहित का ग्रेड,+ कॉन्ट्रैक्ट उनके टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भी जारी रहेगी। वे अभी भी भारतीय क्रिकेट का हिस्सा हैं और उन्हें ग्रेड ए+ में मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी।

5 दिन के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। रोहित ने 7



और कोहली ने 12 मई को टेस्ट से संन्यास लिया था। वहीं, दोनों ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। ग्रेड ए+ में 4 खिलाड़ी बीसीसीआई ने 21 अप्रैल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। ग्रेड ए+ में कोहली और रोहित के अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा हैं। बीसीसीआई ग्रेड ए+ में हर खिलाड़ी को सालाना 7 करोड़ रुपए देती है।बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों में 34 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पिछले साल 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वहीं ग्रेड,+ में पिछले साल की तरह चार खिलाड़ी ही हैं। ग्रेड, में 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पिछली बार भी इस कैटेगरी में 6 खिलाड़ी थे। वहीं क्रम में पिछली बार की तरह पांच खिलाड़ी और छ में 19 खिलाड़ी हैं। पिछली बार 15 खिलाड़ी शामिल किए गए थे।

जडेजा लगातार 1151 दिन तक नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर सबसे लंबे समय तक टॉप पर रहने वाले प्लेयर बने

नई दिल्ली। आईसीसी ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में रवींद्र जडेजा सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 पर रहने वाले प्लेयर बने हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में 1151 दिनों और 38 महीने से ऑलराउंडर के रैंकिंग के टॉप पर काबिज है।

जडेजा का पिछले साल शानदार सीजन रहा, उन्होंने 29.27 की औसत से 527 रन बनाए। साथ ही 24.29 की औसत से 48 विकेट भी झटकें। जडेजा ने जैक्स कैलिस, कपिल देव, इमरान खान जैसे खिलाड़ी को पीछे छोड़ा। उन्होंने 9 मार्च 2022 की रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल किया था। जडेजा ने वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर को पीछे छोड़ा था।



उनके बाद बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज (327 पॉइंट्स) और मार्को यानसन (294 पॉइंट्स) हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कर्मिस और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि टॉप 10 में जडेजा इकलौते भारतीय ऑलराउंडर हैं।

जडेजा मार्च 2022 में नंबर-1 रैंकिंग में पहुंचे थे। तब से अब तक जडेजा ने 23 टेस्ट मैचों में 1175 रन बनाए हैं। इसमें उनका औसत 36.71 का रहा। इसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। बॉलिंग में उन्होंने स्पिन से 91 विकेट लिए, औसत 22.34 का रहा, जिसमें 6 बार 5 विकेट और 2 बार 10 विकेट लेने शामिल हैं।

400 रेटिंग के साथ नंबर-1 पर बुधवार को जारी टेस्ट रैंकिंग पॉइंट के साथ नंबर-1 पर हैं।

युवराज के पिता ने विराट-रोहित के संन्यास को बताया गलत, बोले-दोनों में क्रिकेट बाकी था

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बयान दिया है। योगराज सिंह ने कहा- कोहली और रोहित शर्मा में अभी काफी क्रिकेट बाकी है, मगर उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी देश के बड़े खिलाड़ियों में से हैं। ऐसे में भारत को इसका जाहिर तौर पर नुकसान होना तय है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में ये बयान दिया।

योगराज बोले- मैंने युवराज को संन्यास लेने से मना किया था योगराज सिंह ने कहा- विराट और रोहित देश की क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। इसलिए उनके जाने पर भारतीय टीम को नुकसान होगा। जब 2011 में कई खिलाड़ियों को या तो हटा दिया गया और या फिर कई ने संन्यास ले लिया। कई खिलाड़ियों तो जबर्न



संन्यास के लिए मजबूर किया गया, तो टीम बिखर गई और अब तक उबर

नहीं पाई है। लेकिन हर किसी का समय आता है।

योगराज सिंह ने आगे कहा- मुझे लगता है कि विराट और रोहित में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। मैंने युवी (युवराज सिंह) से कहा था कि जब वह संन्यास ले रहा था तो यह सही कदम नहीं था। जब कोई चल नहीं सकता तो उसे मैदान छोड़ देना चाहिए। यदि आप युवाओं से भरी टीम बनाते हैं, तो वह हमेशा बिखर जाएगी।

योगराज ने आगे कहा- शायद विराट को लगता है कि उनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को रोजाना प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की जरूरत है। रोहित और वीरेंद्र सहवाग दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी संन्यास ले लिया। बड़े खिलाड़ियों को 50 साल की उम्र तक खेलना चाहिए, मैं उनके संन्यास से दुखी हूं, क्योंकि अब युवाओं को प्रेरित करने वाला कोई नहीं बचा है।

लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन बैडमिंटन से बाहर, राजावत भी राउंड-1 में हारे

घोलपुर। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत थाईलैंड ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं। वहीं, आकर्षि कश्यप और उन्नति हुड्डा इस सुपर 500 टूर्नामेंट में कड़े मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं।

बुधवार को सेन को आयरलैंड के एन एंगुयेन ने एक घंटे 20 मिनट तक चले मैच में 18-21, 21-9, 17-21 से हराया। पहला गेम हारने के बाद सेन ने दूसरे गेम में वापसी की, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम में एंगुयेन ने उन्हें उबरने का मौका ही नहीं दिया।

मैस सिंगल्स कैटेगरी में प्रियांशु राजावत को भी पहले दौर में पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के अल्वी फरहान ने 21-13, 17-



21, 21-16 से मात दी। इस मुकाबले में प्रियांशु ने बड़े अंतर से गंवाया, लेकिन दूसरे गेम में शानदार कोर्ट कवरेज और दमदार खेल की बदौलत विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में आकर्षि

कश्यप ने जापान की कोआरु सुगियामा को 21-16, 20-22, 22-20 से हराया। वहीं, उन्नति ने थाईलैंड की थामोवान एन को 21-14, 18-21, 23-21 से मात दी। रश्मिता श्री संतोष रामराज पहले दौर में सिंगापुर की थिओ जिया मिन से 18-21, 7-21 से हार गईं।

रियो ओलिंपिक 2016 में गोल्ड जीतने वाले अमेरिकी रसलर काइल स्नायडर को कोलंबस पुलिस ने प्रॉस्टिट्युशन के मामले में गिरफ्तार किया है। वे शुक्रवार रात को एक प्रॉस्टिट्युशन से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे। हालांकि, पुछताछ के बाद स्नाइडर को मौके से ही छोड़ दिया। अब उन्हें 19 मई 2025 को अदालत में पेश होना होगा

व्यापार

फाइटर-जेट तेजस बनाने वाली कंपनी हाल का मुनाफा 8 प्रतिशत घटा

रेवेन्यू 7 प्रतिशत घटकर 13,700 करोड़ रुपए रहा कंपनी का शेयर एक साल में 17 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। फाइटर जेट तेजस और ध्रुव हेलिकॉप्टर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 3,977 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा (कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट) हुआ है। सालाना आधार पर यह 8व घटा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,309 करोड़ रुपए था।

जनवरी-मार्च तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 13,700 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 14,769 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था।



सालाना आधार पर यह 7.23 प्रतिशत घटा है।

वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। हाल ने आज मंगलवार (13 मई) को जनवरी-मार्च तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का टोटल इनकम मुनाफा मार्केट विश्लेषकों की उम्मीद से कम रहा है, यानी कंपनी ने इस बार बेहतर काम नहीं किया है।

हाल का शेयर 3.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,779.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर एक महीने में 14 प्रतिशत और 6 महीने में 16.94 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में कंपनी का शेयर 17.30 प्रतिशत बढ़ा है। हाल का मार्केट कैप 3.18 लाख करोड़ रुपए है।

कॉन्सोलिडेटेड मुनाफा मतलब पूरे ग्रुप का प्रदर्शन

कंपनियां के रिजल्ट दो भागों में आते हैं- स्टैंडअलोन और कॉन्सोलिडेटेड। स्टैंडअलोन में केवल एक यूनिट या सेगमेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। जबकि, कॉन्सोलिडेटेड या समेकित फाइनेंशियल रिपोर्ट में पूरी कंपनी का डेटा जारी होता है।

चौथी तिमाही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की टोटल इनकम सालाना आधार पर 6.36 प्रतिशत घटकर 14,351 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 15,326 करोड़ रुपए रही थी।

एयरटेल का चौथी तिमाही में मुनाफा 432 प्रतिशत बढ़ा, ये 11,022 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 11,022 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा (कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट) हुआ है। सालाना आधार पर यह 432 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,072 करोड़ रुपए था।

जनवरी-मार्च तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 47,876 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में एयरटेल ने 37,599 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था।



सालाना आधार पर यह 27 प्रतिशत बढ़ा है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। भारती एयरटेल ने आज मंगलवार (13 मई) को जनवरी-मार्च तिमाही और सालाना

नतीजे जारी किए हैं। नतीजों में आम आदमी के लिए क्या?

कंपनी ने वित्त-वर्ष 2024-25 के लिए हर शेयर पर 16 रुपए फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश देने का ऐलान किया है। कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयरहोल्डर्स को देती हैं, इसे डिविडेंड या लाभांश कहा जाता है। भारती एयरटेल का शेयर 2.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,824.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर एक महीने में 2 प्रतिशत और 6 महीने में 18 प्रतिशत

बढ़ा है। एक साल में कंपनी का शेयर 42 प्रतिशत बढ़ा है। भारती एयरटेल का मार्केट कैप 10.91 लाख करोड़ रुपए है।भारत सरकार ने 1992 में पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटने शुरू किए। कंपनी के फाउंडर सुनील मित्तल ने इस अवसर को समझा और फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आस-पास के इलाकों के लाइसेंस हासिल किए। 1995 में मित्तल ने सेल्युलर सर्विस ऑफर करने के लिए भारती सेल्युलर लिमिटेड बनाई और एयरटेल ब्रांड के तहत काम शुरू किया।

नई दिल्ली। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय डिफेंस स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। बुधवार, 14 मई को कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के शेयर 17 प्रतिशत तक चढ़े। जबकि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 3व की तेजी रही। ब्रोकरेज फर्मस का मानना है कि सरकारी ऑर्डर बढ़ने, घरेलू उत्पादन पर फोकस और निर्यात में बढ़ोतरी के चलते डिफेंस स्टॉक्स लगातार निवेश हो रहा है। पिछले 1 महीने में कोचीन शिपयार्ड ने 23 प्रतिशत तो वहीं पारस डिफेंस जैसे शेयर ने 42 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

पीएसयू डिफेंस स्टॉक गार्डन रीच



शिप बिल्डर्स 16 प्रतिशत तेजी के साथ 2,212 रुपए पर बंद हुआ। वहीं कोचीन शिपयार्ड का शेयर में 8 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,699 रुपए पर बंद हुआ। मझगांव डॉक और पारस डिफेंस के शेयर में 4 प्रतिशत

की तेजी रही। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने एफवाई25 में 48 प्रतिशत की उछाल के साथ 527 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। चौथी तिमाही में लाभ 118 प्रतिशत बढ़कर 244

करोड़ रुपए रहा। इसके चलते शेयर में पिछले एक साल में 125 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

डिफेंस सेक्टर में तेजी की मुख्य वजह एफवाई 27 तक 8.45 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की संभावना है। डिफेंस एंकिजिशन काउंसिल ने हाल ही में टी-90 टैंक इंजन, वरुणास्त्र टॉरपीडो समेत 54,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। एंरिक स्टॉक ब्रोकिंग के अनुसार, सरकार के मेक इन इंडिया पुरा और घरेलू उत्पादों पर जोर देने की नीतियों से शिपयार्ड कंपनियों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा। वर्तमान में देश का 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण स्थानीय स्तर पर बन रहा है।

ग्राम सभाओं के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण को मिलेगा बढ़ावा : कलेक्टर

- सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन एवं समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें अधिकारी: कलेक्टर

- नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जर्जर भवनों का सर्वे कर सीएमओ करें चिन्हित-कलेक्टर

- कलेक्टर हर्षल पंचोली ने समयावधि पत्रों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश

(ब्यूरो राजेश शिवहरे)
अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा कि मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अधिनियम 2022 के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण एवं व्यापार की प्रक्रिया ग्राम सभाओं के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से संचालित की जाए तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण को बढ़ावा मिले। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं का नियमित रूप से आयोजन कर ग्रामीणों को तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। एक सशक्त अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक ग्रामीण इस कार्य से जुड़ें, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर और आय के स्रोत उपलब्ध हो सकें। कलेक्टर हर्षल पंचोली मंगलवार को आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन एवं समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन एवं समय-सीमा में प्राप्त लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं व जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचना चाहिए। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी नियमित रूप से प्रकरणों की

मॉनिटरिंग करें और प्राथमिकता के आधार पर लंबित शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।



जिससे आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों को चिन्हित कर सूची बनाएं तथा यह जानकारी समयबद्ध रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपलब्ध कराएं। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु से पूर्व संभावित जोखिमों का आंकलन कर उनके समाधान हेतु ठोस कार्ययोजना बनाना है। जिससे आगामी दिनों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। कलेक्टर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा कर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कक्षा नवमी एवं दसवीं में

अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची तैयार कर सभी विद्यार्थियों का पुनः नामांकन भरवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे

एवं बाल विकास विभाग से अप्रैल तथा मई माह के टेक होम राशन के आर्बटन तथा वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अप्रैल-मई माह का वितरण शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित ऋक योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी, विशेषकर महिला उद्यमियों को व्यापार,वित्त और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग में मदद करना है।

उन्होंने निर्देश दिए कि ऋकयोजना के प्रशिक्षण हेतु आईटीआई को एक केंद्र के रूप में चिन्हित किया जाए, ताकि प्रशिक्षण की व्यवस्था सुचारु रूप से की जा सके। बैठक में कलेक्टर ने उद्यान विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद के वर्कशॉप का आयोजन, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 के संबंध में चर्चा, मत्स्य विभाग, नल जल योजना,खेत तालाब योजना सहित अन्य विभिन्न विभागों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी अंजली द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा अजीत तिकी,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्परजगद सुधाकर सिंह बघेल सहित जिले के विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को निर्देश दिए कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सभी पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं शैक्षणिक सामग्री का वितरण समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में शासकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विद्यालय परिसरों में शौचालयों की मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में महिला

थाना बिजुरी द्वारा रात्रि कॉबिंग गरस्त के दौरान 08 गिरफ्तारी वारंट की तामीली

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान द्वारा जिले में अपराधों में नियंत्रण हेतु सोमवार की रात्रि जिले के समस्त थानों में कॉबिंग गरस्त कराई गई जिसमें फरार चल रहे गिरफ्तारी वारंटी की तामीली जिला बदल आरोपियों की घर चेकिंग, निगरानी एवं गुण्डा बदमाशों की चेकिंग एवं वसूली वारंटी की तामीली हेतु निर्देशित किया गया। सोमवार की रात्रि दिनांक 12/05/2025 को थाना बिजुरी पुलिस द्वारा रात्रि कॉबिंग गरस्त के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मन्सूरी एवं एसडीओपी कोतमा आरती शायक के निर्देशन में थाना प्रभारी बिजुरी विकास सिंह , सर्जन उदय प्रजापति,सर्जन कमलेश शुक्ला,आर.प्रभाकर त्रिपाठी, रामनिवास गुर्जर, म.आर. संगम तोमर

की अलग अलग पार्टीयों ने वाटेड निवासी मोहाडा दफाई बिजुरी को



अपराधियों की घेराबंदी की जाकर फरार चल रहे 4 वारंटीयों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से विनय बंसल पिता शुभगलाल बंसल उम्र 28 वर्ष

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने किया बीज उत्पादक सहकारी संस्था परसवार का निरीक्षण



- किसानों की आय बढ़ाने एवं संस्था को मल्टीपरपज बनाने के दिए निर्देश

अनूपपुर।कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम दुलहरा स्थित जागुति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित परसवार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे बीज उत्पादन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। समिति के अध्यक्ष ने कलेक्टर को अवगत कराया कि इस संस्था में कुल 8 ग्राम के 57 किसान सम्मिलित हैं तथा यहां मुख्य रूप से धान, गेहूं एवं दाल के बीज तैयार किए जाते हैं। कलेक्टर पंचोली ने संस्था के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी संस्था ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि हेतु प्रयास करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संस्था को मल्टीपरपज सहकारी संस्था के रूप में विकसित किया जाए, ताकि केवल सीमित बीजों तक न रहकर अन्य फसलों के बीज उत्पादन की दिशा में भी कार्य किया जा सके। इससे संस्था की कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा।

डेयरी व्यवसाय से आत्मनिर्भर बने किसान दीनबंधु पटेल, कलेक्टर ने किया सराहना

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलहरा का भ्रमण कर आचार्य विद्यासागर योजना से लाभान्वित कृषक श्री दीनबंधु पटेल की डेयरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसान श्री पटेल ने कलेक्टर को जानकारी

दी कि उन्हें आचार्य विद्यासागर योजना के अंतर्गत शासन से 6 गायें प्राप्त हुई थीं, जिनसे उन्होंने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। वर्तमान में वे प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं तथा प्रति माह लगभग 20 से 25 हजार रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। कलेक्टर पंचोली ने किसान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के अन्य पात्र किसानों को भी आचार्य विद्यासागर योजना का लाभ दिलाया जाए, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान अधिकारियों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि किसान दीनबंधु पटेल को वर्ष 2023-24 में 'गोपाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। किसान की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कलेक्टर ने उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर ने दारसागर में 12 किसानों द्वारा 15 एकड़ भूमि में की जा रही उन्नत खेती का किया निरीक्षण

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम दारसागर में कृषक विनय पटेल सहित अन्य 12 किसानों द्वारा 15 एकड़ भूमि में की जा रही टमाटर एवं करेला की उन्नत खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों के नवाचार और मेहनत की सराहना करते हुए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दारसागर को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए कलेक्टर के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार करने और उन्नतशील किसानों को खेती,

पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसी पहल जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेंगी और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।

कलेक्टर ने दारसागर के कृषक बृजभान सिंह की लेमनग्रास खेती का किया निरीक्षण

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आज ग्राम दरसागर के कृषक बृजभान सिंह द्वारा 8 एकड़ क्षेत्र में की जा रही लेमनग्रास (सुगंधित पौधा) की खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को अवगत कराया गया कि कृषक श्री बृजभान विगत कई वर्षों से लेमनग्रास की खेती कर रहे हैं तथा उन्होंने पिछले वर्ष लगभग 1.50 लाख रुपये की आय प्राप्त की है। कलेक्टर ने कृषक के नवाचार की प्रशंसा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्य कृषकों को भी लेमनग्रास जैसी औषधीय एवं लाभकारी फसलों की खेती हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसल प्रणाली को अपनाकर कृषकगण अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर गुना, पशु चिकित्सा अधिकारी अनूपपुर, आत्मा परियोजना की सहयोग परियोजना अधिकारी निशा सिन्हा सहित अन्य अधिकारी, हितग्राही एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन में कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशन में अनूपपुर जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर

अनूपपुर। ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन में अनूपपुर जिले ने मध्यप्रदेश में चौथा स्थान बनाया है। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशन, मार्गदर्शन में अनूपपुर जिले को यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

अनुकंपा नियुक्ति के लिये मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित

ग्वालियर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों की मूल्य उपरांत उनके आश्रित सदस्य को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। कंपनी ने कहा है कि उक्त कार्य में विलंब न हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयवधि में कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिये मानक संचालन प्रक्रिया को कंपनी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के वृत्त तथा क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

263 ग्राम पंचायतों में तेजी से आकार ले रही हैं जल संरचनायें

ग्वालियर। जिले की सभी 263 ग्राम पंचायतों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरचनायें तेजी से आकार ले रही हैं। कार्यों में तेजी आने से इस अभियान में जिले की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्वालियर जिला अब जल गंगा संवर्धन अभियान में 11वे पायदान पर आ गया है। कहीं पर खेत तालाब, कहीं पर अमृत सरोवर तो कहीं पर पुराने कुँओं के पुनर्भरण के लिये संरचनायें बनाई जा रही हैं। साथ ही पिछले वर्षों की जल संरचनाओं को पूरा करने का काम भी अभियान के तहत हो रहा है। जिले की 263 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में वर्षा जल सहेजने के लिये 1610 कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 832 पुरानी जल संरचनाओं को पूरा करने का काम भी प्रमुखता से कराया जा रहा है।

ग्रामीणों को अपने गाँव की जल



जल गंगा संवर्धन अभियान में जन-जन की भागीदारी के उद्देश्य से रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जल संचय एवं उपयोग के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जगह-जगह समूहों की बैठक लेकर

संरचनाओं को सहेजने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी रविन्द्र सिंह जादौन ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कुल 854 खेल तालाब स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 794 खेत तालाबों का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह जिले में 903 पुराने कुँओं की रिचार्ज करने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 810 कुँओं की रिचार्ज करने के लिये संरचनायें बनाने का काम जारी है। जिले में 6 अमृत सरोवर भी स्वीकृत किए गए हैं। जिले में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही जल संरचनायें जल संरक्षण व संवर्धन का काम तो कर ही रही हैं, साथ ही मछली पालन व सिंचाई उत्पादन जैसी व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों की अतिरिक्त आय का साधन भी बनेंगीं। खेत तालाबों व अमृत सरोवरों के किनारे वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के काम भी किए जायेंगे।

ग्वालियर । शासन व प्रशासन का दायित्व केवल अधोसंरचनागत कार्यों तक ही सीमित न होकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ना व रचनात्मक कार्य करना भी है। इसी भाव के साथ उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति आनंद पाठक की प्रेरणा से कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गजराजा अर्पण आश्रम अर्थात मर्सी होम का समाज के सहयोग से कायाकल्प करने की पहल की है। मर्सी होम के कायाकल्प के पीछे उद्देश्य यह है कि यहाँ निवासरत मानसिक दिव्यांग जरूरतमंद बच्चों का जीवन स्तर उँचा उठे और उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छा माहौल मिले।

जिला प्रशासन का प्रयास है कि मर्सी होम का परिसर ऐसा रूप ले जिससे यहाँ निवासरत मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को साफसुथरा, आकर्षक व प्रेरणादायी वातावरण मिले। शहर में स्थित अलापुर पहाड़ी को वृहद वृक्षारोपण के जरिए -हरि पर्वत- के रूप में अंकित करने में योगदान दे रही राम आस्था मिशन संस्था मर्सी होम के



कायाकल्प में सहयोग देने के लिये आगे आई है। मर्सी होम परिसर की दीवारों का रंग-रोगन कर व आकर्षक एवं प्रेरणादायी पेंटिंग कर सजाया व सँवारा जा रहा है। दीवारों पर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जा रही है, जिससे मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हो। उच्च न्यायालय द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को समाज की मुद्दखधारा में शामिल करने के संबंध में दिए गए आदेशों को निर्धारित समयवधि में कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिये मानक संचालन प्रक्रिया को कंपनी की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के वृत्त तथा क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

बिछुड़ों को अपनों से मिला रही है ग्वालियर की पहल

ग्वालियर । अपनों से बिछुड़े बच्चों व लोगों को उनके माता-पिता एवं परिजन से मिलाने में ग्वालियर जिले में हुआ नवाचार महती भूमिका निभा रहा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों व अन्य लोगों के आधारकार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। आधारकार्ड बनाने की इस पहल ने बिछुड़े बच्चों के घर का पता व परिजनों को ढूँढ़ने में बड़ी मदद की है। डबरा स्थित +अपनी घर आश्रम+ सहित जिले के अन्य आश्रय गृहों में रह रहे कई लोगों को इस पहल के माध्यम से फिर से अपनों के बीच पहुँचाने में मदद मिली है। ग्वालियर जिले की इस पहल से

प्रेरित होकर राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में आश्रय गृहों में निवासरत बिछुड़े बच्चों के आधारकार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सभी जिलों के लिये इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की है। कलेक्टर श्रीमती चौहान के निर्देश पर जब अपना घर आश्रम सहित जिले के अन्य आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों व अन्य लोगों के नए आधारकार्ड बनाने के लिये बायोमेट्रिक अर्थात अंगुलियों के निशान लिए गए तब कुछ लोगों के ऑनलाइन आधार आवेदन निरस्त हो गए। कारण बताया गया कि इनका

आधारकार्ड पहले से ही बना है। पुराने आधार नम्बर के माध्यम से इन लोगों के घर व परिजनों का पता मिल गया। ऐसे लोगों व बच्चों के माता-पिता एवं परिजनों को बुलाया गया। इस प्रकार आधारकार्ड ने बिछुड़े हुए लोगों का पुनर्मिलन करा दिया। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जिले के सभी आश्रय गृहों में निवासरत शतप्रतिशत रहवासियों के आधार पंजीयन कराने के निर्देश दिए, जिससे यदि किसी का पहले से आधार नम्बर हो तो उनके घर का पता लगाया जा सके। साथ ही रहवासियों को आधारकार्ड के आधार पर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

सड़क घेर रहे ठेले वालों को हटा वसूला जुर्माना



अंतर्गत फूलावण चौराहे से गरुद्वारे चौराहे तक पुर्चाथियों द्वारा पुर्चापा घेर कर किया गया अतिक्रमण को हटाय़ा जाकर सामान जल्द कर, पुर्चापा खाली कराय़ा गया तथा 1 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद चौराहे, अक्लेधर चौराहा एवं मोर्दे की माता से नाकाचंदकनी तिराहा तक यातायात अवरुद्ध कर रहे हाथ ठेले और गुम्टी वालों को हटाय़ा गया।

शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा

ग्वालियर। नर्सिंग छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री एवं रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सज रजिस्ट्रेशन कार्डसिल भोपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि दिसंबर 2024 में जीएनएम थर्ड ईयर एवं सेकंड ईयर की हूँ मुख्य परीक्षा के परिणाम आज 5 माह से अधिक का समय हो जाने पर भी घोषित नहीं हुये है। उक्त परीक्षा परिणाम को यथाशीघ्र घोषित किया जाये। छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह गुर्जर ने मांग की है कि छात्र हित में जीएनएम थर्ड ईयर की परीक्षा

नर्सिंग छात्र स्टूडनर्स के पद के लिए बिहार राज्य में प्रकाशित रिक्त के लिए आवेदन कर सकें। वहीं जीएनएम सेकंड ईयर की परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित कर उनके आगामी समय पर निर्गत कर दिए जाएँ। वहीं उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों के मार्कशीट नर्सज कार्डसिल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा संबंधित कॉलेज में भेजे जा चुके हैं।

